

[2023] 3 एस सी आर 310

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

ए.

आय कर के आयुक्त 7

बनाम

मेसर्स पैविल प्रोजेक्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (2021 की सिविल अपील संख्या 6126)

बी.

अप्रैल 06, 2023

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 -s.263-के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग-प्रत्यर्थी ने AY 2007-08 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल किया, जिसमें उसने संपत्ति/भवन की बिक्री को Rs.33 करोड़ की राशि के लिए दिखाया-निर्धारिती के अनुसार, संपत्ति को शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए बिक्री आय से बोझ का निर्वहन करने के लिए बेचा गया था और इसलिए, बोझ का उक्त निर्वहन "सुधार की लागत" था-ए. ओ. यू/एस. द्वारा मूल्यांकन स्वीकार किया गया। 143(3) - हालाँकि, आयुक्त ने यू/एस के अधिकार क्षेत्र को लागू किया। 263 आई. टी. अधिनियम और अभिनिर्धारित किया कि मूल्यांकन आदेश यू/एस. द्वारा पारित किया गया। 143(3) आई. टी. अधिनियम का प्रावधान गलत था और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था-आयुक्त ने ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश को अपास्त करना दिया-आई. टी. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि आयुक्त ने गलत तरीके से यू/एस. के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया। 263 आई. टी. अधिनियम और निर्धारिती के दावे की अनुमति को बरकरार रखा-आई. टी. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:में निर्धारित कानून को लागू करना

सी.

डी.

ई.

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड का मामला और के अवलोकन पर

मूल्यांकन आदेश के साथ-साथ आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश, न्यायालय की राय है कि मूल्यांकन आदेश न केवल गलत था, बल्कि राजस्व के हित के लिए भी प्रतिकूल था-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुक्त ने यू/एस के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया।²⁶³ इसमें निहित नहीं-उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करना दिया गया और यह कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया।²⁶³ आयकर अधिनियम को बहाल किया गया है।

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** यह सच है कि मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड में आयकर अधिनियम की धारा **263** की व्याख्या में यह कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा **263 (1)** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए आयुक्त को संतुष्ट होना होगा।

एच.

310 ए.

311

आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड।

दो शर्तों में से, अर्थात् **(i)** मूल्यांकन अधिकारी का संशोधित करने का आदेश गलत है; और **(ii)** यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है। यह भी देखा गया है कि यदि उनमें से कोई एक अनुपस्थित है, तो अधिनियम की धारा **263 (1)** का सहारा नहीं लिया जा सकता है। [पैरा **7.1**] [318-ई-एफ]

2. यहां तक कि मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड के मामले में भी देखा गया है कि अधिनियम की योजना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाने और एकत्र करने की है और यह कार्य राजस्व को सौंपा गया है। यह भी देखा गया है कि यदि आयकर अधिकारी के गलत आदेश के कारण, राजस्व किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी रूप से देय कर खो रहा है, तो यह निश्चित रूप से राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होगा। हालांकि, केवल उस मामले में जहां दो विचार संभव हैं और निर्धारण अधिकारी ने एक दृष्टिकोण अपनाया है, ऐसा निर्णय, जो प्रशंसनीय हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ है, ऐसे आदेश पर धारा **263** [पैरा **7.2**] [320-ए-सी] के तहत पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

3. निर्धारण आदेश के साथ-साथ आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को देखने के बाद, हमारी यह भी राय है कि निर्धारण आदेश न केवल गलत था, बल्कि राजस्व के हित के लिए भी प्रतिकूल था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुक्त ने धारा **263** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो इसमें निहित नहीं था। [पैरा **7.3**]
[320-डी-ई]

ई.

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. **(2000) 2 एस. सी. सी. 718**
:[2000] 1 एससीआर 744:(2000) 243 आईटीआर 83 (एससी)-पर निर्भर था।

एफ.

सी. आई. टी. बनाम श्रीमती शकुंतला कांतिलाल **(1991) 190 आईटीआर 56 (बॉम्बे);**
केमोसिन लिमिटेड। बनाम एसीआईटी **(2012) (25)**

टैक्समैन। कॉम **325 (बॉम्बे)-संदर्भित।संदर्भित निर्णय**

[2000] 1 एससीआर 744

पर भरोसा किया गया |

पैरा. **3.4,7.2,7.3**

जी.

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील संख्या 6126।

2015 के आई. टी. ए. No.78 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2017 से।

एच.

312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

ए.

बीर सिंह, ए. एस. जी., पीयूष बेरीवाल, सुश्री चिन्मायी चंद्र, श्याम गोपाल, श्याम, मनीष, राज बहादुर यादव, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

फिरोज अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता, मानेक अंधारुजिना, निरव बी. मर्चेट, राजेश कुमार, विनोद कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था बी.

एम. आर. शाह, जे.

1. 2015 के आई. टी. ए. आई. डी. 1 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है, राजस्व ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

सी.

2. वर्तमान अपील से संबंधित प्रासंगिक मूल्यांकन आदेश मूल्यांकन वर्ष 2007-08 है।

डी.

3. प्रत्यर्थी निर्धारिती वस्त्रों, जूतों आदि के निर्माण और निर्यात में लगा हुआ था। इसने ए. वाई. 2007-08 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल किया जिसमें उसने संपत्ति/भवन "पैविल हाउस" की Rs.33 करोड़ की राशि में बिक्री दिखाई। कि, भवन "पैविल हाउस" का निर्माण निर्धारिती द्वारा भूमि के टुकड़े पर किया गया था जिसे वर्ष 1972 में खरीदा गया था। कंपनी के उक्त घर को कंपनी की तुलनपत्र में विधिवत दर्शाया गया था।

ई.

3.1 ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के शेयरधारकों के परिवार के सदस्यों के बीच मुकदमेबाजी हुई थी। कंपनी विधि बोर्ड और उच्च न्यायालय में मुकदमों का समापन मध्यस्थता में हुआ। मध्यस्थता कार्यवाही में, एक अंतरिम निर्णय पारित किया गया था जिसके तहत पक्षों के बीच "पारिवारिक समझौता" नामक एक सौहार्दपूर्ण समझौता दर्ज किया गया था। अंतरिम पुरस्कार के अनुसार, तीन शेयरधारक अर्थात् (1) आशा, (2) नंदिता और (3) निखिल को रु। 10.35 प्रत्येक करोड़। निर्धारिती के अनुसार, "पैविल हाउस" को शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए बिक्री आय से बोझ का निर्वहन करने के लिए बेचा गया था और इसलिए, बोझ का उक्त निर्वहन "सुधार की लागत" था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, "पैविल हाउस" को Rs.33 करोड़ की राशि में बेचा गया था। निर्धारिती ने एवाई 2007-08 के लिए अपनी आय की गणना में "दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ" के रूप में रुपये 1,21,16,695/- से उत्पन्न होने वाले लाभ को दिखाया। पूंजीगत लाभ की कार्यात्मक गणना ए. ओ. द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत बोझ को दूर करने की लागत ए.

एफ.

जी.

एच.

313

आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

दावा किया गया (रु। अंतरिम अधिनिर्णय के अनुसार तीन शेयरधारकों को भुगतान किए गए करोड़ रुपये) को "सुधार की लागत" के रूप में लिया गया था और कटौती का दावा पूंजीगत लाभ की गणना पर बोझ को दूर करने के लिए किया गया था। शेष राशि पर पूंजीगत लाभ कर की पेशकश की गई और भुगतान किया गया। आय की गणना में संलग्न पत्रक के अनुसार "दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ" को स्वीकार करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) (संक्षेप में "आईटी अधिनियम") के तहत एओ द्वारा आकलन 15.12.2019 पर पूरा किया गया था।

बी.

3.2 हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत आयकर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.10.2011 का एक नोटिस जारी किया गया था ताकि यह बताया जा सके कि आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत मूल्यांकन आदेश को क्यों अपास्त करना नहीं किया जाना चाहिए। आयुक्त ने अपने दिनांक 24.11.2011 के आदेश के माध्यम से कहा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत पारित मूल्यांकन आदेश गलत था और रुपये की कटौती से संबंधित मुद्दे पर राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करते समय सुधार की लागत के रूप में निर्धारिती द्वारा दावा किए गए करोड़ रुपये। निर्धारिती का यह दावा कि उक्त भुगतान उनके द्वारा मुकदमे के निपटारे के लिए किया गया था, जो निर्धारिती के अनुसार बोझों के निर्वहन के बराबर था और जिसे सुधार की लागत के रूप में माना जाना आवश्यक था, आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उनके अनुसार यह आई. टी. अधिनियम की धारा 55 (1) (बी) में निहित "सुधार की लागत" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। आयुक्त के अनुसार, निर्धारिती द्वारा दावा किए गए खर्चों में न तो पूंजी प्रकृति का खर्च होता है और न ही इसके परिणामस्वरूप कोई परिवर्धन या परिवर्तन होता है जो पूंजी परिसंपत्ति को स्थायी प्रकृति का वर्धित मूल्य प्रदान करता है। आयुक्त ने यह भी कहा कि जैसा कि तर्क दिया गया है, भुगतान निर्धारिती द्वारा बोझ को दूर करने के लिए नहीं किया गया था।

सी.

डी.

ई.

3.3 आयुक्त ने यह भी कहा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 50 ए और 55 (1) (बी) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और मूल्यांकन आदेश आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बनाया गया है और इस प्रकार मूल्यांकन आदेश गलत था और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था। नतीजतन, आयुक्त ने ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश अपास्त करना कर दिया, जिसमें ए. ओ. को आदेश में चर्चा किए गए आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारिती के पूंजीगत लाभ की पुनः गणना करने का निर्देश दिया गया था।

एफ.

जी.

3.4 निर्धारिती ने आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आई. टी. ए. No.16/MUM/2012 दाखिल करके आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "आई. टी. ए. टी.") का दरवाजा खटखटाया। आई. टी. ए. टी. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

एच.

314 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (2000) 2 एस. सी. सी.
718:(2000)

243 आई. टी. आर. 83 (एस. सी.) ने निष्कर्ष निकाला कि आयुक्त ने आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया। आई. टी. ए. टी. ने यह भी पाया कि घोषित तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं थी। आई. टी. ए. टी. ने कहा कि ए. ओ. के आदेश के परिणामस्वरूप राजस्व के प्रत्येक नुकसान को राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, जब दो विचार संभव थे और ए. ओ. ने एक दृष्टिकोण अपनाया जिससे सी. आई. टी. सहमत नहीं था। आई. टी. ए. टी. ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर शेयरधारकों को किए गए भुगतान की कटौती के निर्धारिती के दावे की अनुमति को भी बरकरार रखा।

बी.

सी. आई. टी. बनाम में न्यायालय। शकुंतला कांतिलाल [(1991) 190 आईटीआर 56 (बॉम्बे)]। न्यायाधिकरण के आदेश पर भरोसा करते हुए आई. टी. ए. टी. (बॉम्बे बेंच)

सी.

(बॉम्बे)] ने माना कि शेयरधारकों के भुगतान के लिए किए गए व्यय के बारे में सी. आई. टी. का अवलोकन गलत के रूप में कटौती योग्य नहीं है।

3.5 आई. टी. ए. टी. के आदेश के खिलाफ विभाग की अपील को उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया है जिसमें उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. के निष्कर्षों की पुष्टि की है। उच्च न्यायालय आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत था कि 500 करोड़ रुपये की कटौती का दावा। 31.05 करोड़ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए थे और मुकदमेबाजी केवल तभी समाप्त हुई जब इमारत को बेच दिया गया था और भुगतान कंपनी लॉ बोर्ड के निर्देश के साथ-साथ अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार किया गया था और इसलिए, इसे आईटी अधिनियम की धारा 55 (1) (बी) के तहत कटौती योग्य था, जैसा कि एओ द्वारा अनुमति दी गई थी।

डी.

ई.

3.6 राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसके द्वारा आई. टी. ए. टी. ने आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत आयुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया था, राजस्व ने वर्तमान अपील दायर की है। 4. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज करने और आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में भौतिक रूप से गलती की है, जिसके द्वारा आई. टी. ए. टी. ने आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया था।

एफ.

जी.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि ए. ओ. द्वारा रुपये के खर्च की अनुमति देने में लिया गया दृष्टिकोण। 31.05 भूमि की बिक्री से पूंजीगत लाभ की गणना करते समय करोड़ रुपये गलत थे और कानून के अनुसार शेयरधारकों को किए गए भुगतान के रूप में नहीं थे

एच.

आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

न तो खर्च हैं और न ही उक्त भुगतानों का विचाराधीन संपत्ति से कोई संबंध है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से इस बात की सराहना नहीं की है कि निर्धारिती का दावा है कि रु। 31.05 मुकदमेबाजी के निपटारे के बदले में उसके द्वारा भुगतान किए गए करोड़ रुपये बोझों के निर्वहन के बराबर होंगे और इसलिए, इसे माना जाना चाहिए क्योंकि उक्त संपत्ति पर सुधार की लागत कानूनी रूप से खराब है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रुपये का भुगतान। 31.05 शेयरधारकों को दिए गए करोड़ रुपये से निर्धारिती द्वारा पहले से अधिग्रहित संपत्ति में किसी भी ब्याज का अधिग्रहण नहीं हुआ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त संपत्ति पर निर्धारिती द्वारा पहले से प्राप्त अधिकार निरपेक्ष थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश गलत, कानूनी रूप से खराब और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था और इसलिए, इसे आयुक्त द्वारा आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत सही ढंग से अपास्त करना दिया गया था, जिसे आई. टी. ए. टी. द्वारा अलग नहीं किया जाना चाहिए था।

बी.

सी.

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आयुक्त ने ठीक ही कहा कि निर्धारिती कंपनी संपत्ति की स्पष्ट मालिक थी और उक्त संपत्ति की बिक्री को रोकने के लिए कोई बोझ नहीं था। तीन शेयरधारकों के भाई और दो बहनों के बीच पारिवारिक विवाद, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता पुरस्कार के माध्यम से एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार तीन शेयरधारक रुपये के हकदार बन गए। 10.35 शेयरों के हस्तांतरण के साथ-साथ किसी भी अधिकार को छोड़ने या कंपनी में अतिरिक्त शेयरों के दावे के लिए प्रत्येक करोड़ रुपये का संपत्ति में सुधार से कोई लेना-देना नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शेयरधारकों की केवल चिंता यह थी कि बिक्री आय का उपयोग पहले मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार उन्हें भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि रु। 10.35 करोड़ कटौती के रूप में स्वीकार्य थे।

डी.

ई.

एफ.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. ए. टी. के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने कीमोसिन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर आयुक्त के आदेश को रद्द करने में त्रुटि की है।

और श्रीमती। शकुंतला कांतिलाल (ऊपर), इस बात की सराहना किए बिना कि वर्तमान मामले के तथ्य निर्भर निर्णयों में शामिल तथ्यों के समान नहीं हैं।

जी.

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी बेची गई संपत्ति के हिस्से का उपयोग निर्धारिती के व्यवसाय में किया गया था और इसलिए, बेची गई संपत्ति के उस हिस्से पर पूंजीगत लाभ पर आईटी अधिनियम की धारा 50 ए के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जाना आवश्यक है और इसलिए, आयकर आयुक्त के पूरे आदेश को अपास्त करना नहीं किया जा सकता था।

एच.

316

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

5. वर्तमान अपील का निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री फिरोज अंधारुजिना ने जोरदार विरोध विद्वान है।

बी.

5.1 निर्धारिती की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें आयुक्त द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है कि आयुक्त ने आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत संशोधन शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग विद्वान है।

सी.

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय निर्धारित कानून पर भरोसा करता है

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा

विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन के आदेशों और आयुक्त के आदेश पर उचित रूप से विचार किया और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आयुक्त ने गलत तरीके से आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्ति ग्रहण की।

डी.

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. ओ. द्वारा पारित आदेश आय की वापसी की जांच के बाद पारित एक सुविचारित आदेश था और ए. ओ. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय था और इसलिए, मूल्यांकन आदेश को गलत और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, जिसे आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत आयुक्त द्वारा संशोधन में लिया जाना आवश्यक था।

ई.

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुधार की लागत के रूप में कटौती के दावे की अनुमति पर एओ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण श्रीमती के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा विधिवत समर्थित था। शकुंतला कांतिलाल (ऊपर)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयुक्त यह समझने में विफल रहे कि जब तक शेयरधारकों के दावे संतुष्ट नहीं होते, तब तक संपत्ति के पूरे हिस्से की बिक्री नहीं होती। यह केवल बोझ परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ प्राप्त करने के लिए था कि पक्षों ने मध्यस्थता के माध्यम से निपटान का सहारा लिया। विवाद का निपटारा किया जा रहा है, भुगतान किया जा चुका है, एओ ने सुधार की लागत के रूप में कटौती के दावे की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है। 5.5 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित विद्वान है कि यदि आदेश गलत है लेकिन ए नहीं है

एफ.

जी.

एच.

317

आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल, आयुक्त आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एओ के आदेश के परिणामस्वरूप राजस्व के प्रत्येक नुकसान को राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। जैसा कि देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, यदि एओ ने कानून में अनुमेय पाठ्यक्रमों में से एक को अपनाया है और इसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ है या जहां दो विचार संभव हैं और एओ ने एक दृष्टिकोण लिया है जिससे सीआईटी सहमत नहीं है, तो इसे राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल गलत आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है।

बी.

5.6 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान मामले में कंपनी के शेयरधारकों के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही थी, जिसमें सभी मुकदमे समाप्त हो गए थे और एक अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार दर्ज विद्वान गया था, जिसके तहत पूरे मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा विद्वान गया था और समझौता जो "पारिवारिक निपटान" है, एक अंतरिम पुरस्कार के रूप में लिया गया था और बाद में प्रतिबद्धता की पूर्ति पर अपनी अंतिमता हासिल की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में शेयरधारकों को रु। 10.35 प्रत्येक करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त भुगतान कंपनी द्वारा (i) व्यवसाय के सुचारु संचालन और कामकाज के लिए; (ii) शेयरधारकों के बीच मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए; (iii) कंपनी की संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए; (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के शेयरधारक भाई और दो बहनों के बीच निरंतरता और सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण समझौता हो और (v) संपत्ति पर बोझ को दूर करने के लिए किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए भुगतान की आवश्यकता थी और उच्च न्यायालय और मध्यस्थता पुरस्कार के साथ-साथ स्वयं शेयरधारकों के आदेशों के अनुसार मंजूरी और अनुमोदन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में अंतरिम अधिनिर्णय में एक विशिष्ट खंड था जो कंपनी को देनदारियों का निर्वहन करने के लिए परिसंपत्तियों को बेचने का अधिकार देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता निर्णय के अनुसार, शेयरधारकों के दावों का भुगतान किया जाना चाहिए। यह एक बोझ था जिसे न्यायालय और मध्यस्थता पुरस्कार के आदेशों के अनुसार निर्वहन किया जाना था। "इसलिए पैविल हाउस" को बोझ उठाने के लिए और शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए बिक्री से प्राप्त आय को बेचने की आवश्यकता थी और इसलिए, बोझ का निर्वहन लागत में सुधार था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए शेयरधारकों को भुगतान की गई राशि, जिसे उचित रूप से बोझ को दूर करने के लिए माना गया था, को उचित रूप से कटौती माना गया था, जैसा कि पूंजीगत लाभ की गणना पर बोझ को दूर करने का दावा किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

318

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

5.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आयुक्त ने इस आधार पर आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत अधिकार क्षेत्र को गलत तरीके से ग्रहण किया कि एओ द्वारा पारित आदेश गलत था और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और इस निर्णय पर भरोसा करना

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में न्यायालय ने यह अनुरोध किया है कि बी.

वर्तमान अपील को खारिज करना। 6. सुना है।

7. वर्तमान मामले में, आयुक्त ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विशेष रूप से यह देखते हुए मूल्यांकन आदेश अपास्त करना कर दिया कि मूल्यांकन आदेश गलत होने के साथ-साथ राजस्व के हित के लिए भी प्रतिकूल था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा आयुक्त द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए अपास्त करना कर दिया है कि आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के तहत गलत तरीके से शक्तियों का उपयोग किया है।

सी.

डी.

7.1 निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने मालाबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यह सच है कि उक्त निर्णय में और आयकर अधिनियम की धारा 263 की व्याख्या पर, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए, आयुक्त को दो शर्तों से संतुष्ट होना पड़ता है, अर्थात्, (i) मूल्यांकन अधिकारी का संशोधित करने का आदेश गलत है; और (ii) यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है। यह भी देखा गया है कि यदि उनमें से कोई एक अनुपस्थित है, तो अधिनियम की धारा 263 (1) का सहारा नहीं लिया जा सकता है। "जिसे राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है", उस पर पैराग्राफ में विचार किया गया है।

ई.

एफ.

8 मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में 10 तक, जो हैं -

निम्नानुसार:- "8. "राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल" वाक्यांश कला की अभिव्यक्ति नहीं है और अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसके सामान्य अर्थ को समझते हुए इसका व्यापक महत्व है और यह कर के नुकसान तक ही सीमित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डावजी दादाभाँय

एंड कंपनी बनाम एस. पी. जैन [(1957) 31 आई. टी. आर. 872 (कैल)], सी. आई. टी. बनाम टी. नारायण पाई [(1975) 98 आई. टी. आर. 422 (कांत)] में कर्नाटक उच्च न्यायालय, सी. आई. टी. बनाम गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय। [(1993) 203 आई. टी. आर. 108 (बम)] और सी. आई. टी. बनाम गुजरात उच्च न्यायालय।

जी.

एच.

319

आय कर आयुक्त 7 बनाम एम/एस पैविल परियोजनाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

मिनालबेन एस. पारिख [(1995) 215 आईटीआर 81 (गुजरात)] ने कर के नुकसान को राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल माना।

9. श्री अब्राहम ने वेंकटकृष्ण राइस कंपनी बनाम मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया। सी. आई. टी. [(1987) 163 आई. टी. आर. 129 (एम. ए. डी.)] ने "राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल" की व्याख्या की। उच्च न्यायालय ने कहा:

बी.

“इस संदर्भ में, (इसे) ऐसे कृत्यों या आदेशों की अवधारणा के रूप में माना जाना चाहिए जो राजस्व के प्रशासन के प्रतिकूल हैं। आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कुछ गंभीर त्रुटि होनी चाहिए, जो समान आकलन के लिए एक खराब प्रवृत्ति या पैटर्न स्थापित कर सकती है, जिसे व्यापक रूप से, आयुक्त राजस्व प्रशासन के हितों के लिए प्रतिकूल मान सकते हैं।”

सी.

हमारे विचार में यह व्याख्या योग्यता स्वीकृति के लिए बहुत संकीर्ण है। अधिनियम की योजना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाने और एकत्र करने की है और यह कार्य राजस्व को सौंपा गया है। यदि आयकर अधिकारी के गलत आदेश के कारण, राजस्व किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी रूप से देय कर खो रहा है, तो यह निश्चित रूप से राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होगा।

डी.

10. "राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल" वाक्यांश को निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एक गलत आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए। निर्धारण अधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप राजस्व के प्रत्येक नुकसान को राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, उदाहरण के लिए, जब एक आयकर अधिकारी ने कानून में अनुमेय पाठ्यक्रमों में से एक को अपनाया है और

इसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ है; या जहां दो विचार संभव हैं और आयकर अधिकारी ने एक दृष्टिकोण लिया है जिससे आयुक्त सहमत नहीं हैं, इसे राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल आदेश के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक कि आयकर अधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में अस्थिर न हो। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित नहीं की गई राशि का निर्धारण उसके इस प्रकार के प्रस्ताव पर उसके हाथों में आय के रूप में किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करते हुए पारित आदेश गलत और राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होगा। (रामप्यारी देवी सरावगी बनाम सी. आई. टी. [(1968) 67 आई. टी. आर. 84 (एस. सी.)] और तारा देवी अग्रवाल बनाम सी. आई. टी. [(1973) 3 एस. सी. सी. 482 देखें। 1973 एस. सी. सी. (कर) 318: (1973) 88 आईटीआर 323]।)”

ई.

एफ.

जी.

एच.

320

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

7.2 इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 9 में कहा गया है

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड (ऊपर) का मामला कि

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाना और एकत्र करना है और यह कार्य राजस्व को सौंपा गया है। यह भी देखा गया है कि यदि आयकर अधिकारी के गलत आदेश के कारण, राजस्व किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी रूप से देय कर खो रहा है, तो यह निश्चित रूप से राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होगा। तथापि, केवल ऐसे मामले में जहां दो विचार संभव हैं और निर्धारण अधिकारी ने एक दृष्टिकोण अपनाया है, ऐसा निर्णय, जो प्रशंसनीय हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ है, ऐसे आदेश पर धारा 263 के तहत पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है।

बी.

7.3 मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करना और आयुक्त द्वारा देखे जाने पर भी, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश गलत होने के साथ-साथ राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है।

निर्धारण आदेश के साथ-साथ आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को देखने के बाद, हमारी यह भी राय है कि निर्धारण आदेश न केवल गलत था, बल्कि राजस्व के हित के लिए भी प्रतिकूल था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुक्त ने धारा 263 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो इसमें निहित नहीं था। गलत निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप कर के रूप में राजस्व का नुकसान हुआ है। यहाँ ऊपर वर्णित मामले की परिस्थितियों और तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

सी.

डी.

ई.

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है और आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा बहाल किया जाता है।

एफ.

नतीजतन, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

एच.